Current Affairs search results for tag: economicsbusiness

1. पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई से मिला 'अनुसूचित बैंक' का दर्जा (Dec. 10, 2021)

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में **वन97 कम्युनिकेशंस** की सहायक कंपनी "पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड" को शामिल किया है।
- आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार, अगर आरबीआई संतुष्ट है की बैंक अपने जमाकर्ताओं के हितों के खिलाफ काम नहीं कर रहा है तो उसे दूसरी अनुसूची में शामिल करता है।
- प्रत्येक अनुसूचित बैंक को दो प्रकार की मूल सुविधाएं प्राप्त होती हैं वह आरबीआई से बैंक दर पर ऋण के लिए पात्र हो जाता है और यह स्वचालित रूप से समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त कर लेता है (एक समाशोधन गृह भुगतान, प्रतिभूतियों, या डेरिवेटिव लेनदेन के विनिमय (यानी, निकासी) की सुविधा के लिए गठित एक वित्तीय संस्थान है।)
- इससे पेटीएम को अपने वित्तीय सेवाओं के संचालन का विस्तार करने में मदद मिलेगी। यह पेटीएम को और भी नया करने में मदद करेगा और भारत में वंचित आबादी के लिए और अधिक वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को लाएगा।
- पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पहले, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को 2019 में आरबीआई से शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक का दर्जा मिला था और इस साल की शुरुआत में फिनो पेमेंट्स बैंक को टैग मिला था।

पेमेंट्स बैंक

- [illegible]
- [illegible]-[illegible] [illegible]|
- [illegible] ₹200,000 [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] ₹100 [illegible]
- [illegible] FDI [illegible]
- [illegible]
- [illegible]|
- [illegible]
- [illegible]-[illegible]
- [illegible] 25% [illegible]
- [illegible], 1949 [illegible] 22 [illegible], 2013 [illegible]
- [illegible], [illegible] 2017 [illegible]
- [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

2. आरबीआई विशेष तरलता को 'पुनर्संतुलन' के रूप में तैयार करेगा (Dec. 9, 2021)

[illegible] (RBI) [illegible]-[illegible] (VRRR) [illegible]

[illegible]-[illegible] (VRRR) [illegible] RBI [illegible] 2021 [illegible], [illegible] (RBI) [illegible] 2 [illegible] 2021 [illegible] 14 [illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]

कई विश्लेषकों के अनुसार, यह अपरंपरागत मौद्रिक सहजता से आरबीआई केआसन निकास की शुरुआत है।

आरबीआई तरलता क्यों कम कर रहा है?

भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 18 महीने से चट्टान और कठिन जगह के बीच फंसी हुई है। महामारी, और उसके बाद हुए लॉकडाउन ने राष्ट्रीय आय को प्रभावित किया है और आपूर्ति की कमी के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है।

मुद्रास्फीति, सिद्धांत रूप में, बहुत कम वस्तुओं और सेवाओं का पीछा करते हुए बहुत अधिक नकदी का परिणाम है। उदाहरण के लिए, COVID-19 महामारी के फैलने के बाद से, लोगों को अभी भी दूध, सब्जियां और अंडे जैसी दैनिक आवश्यक चीजें खरीदनी पड़ीं।

लॉकडाउन के कारण, विक्रेताओं को समय पर आपूर्ति नहीं मिल सकी। इसने कीमतों को बढ़ा दिया क्योंकि लोग समय पर आपूर्ति के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करने को तैयार थे।

जैसे-जैसे देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबंदी होती है, और अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे खुलती है, आपूर्ति की कमी हो सकती है और सिस्टम में अतिरिक्त नकदी की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है।

शेष वित्तीय वर्ष के लिए आरबीआई के मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को इसके पहले के 5.1% के अनुमान से बढ़ाकर 5.7% कर दिया गया है।

इस मोड़ पर, आरबीआई की अत्यधिक प्राथमिकता यह है कि स्थिरता और स्थायी विकास पर टिकाऊ प्राप्ति सुनिश्चित किया जाता है।

आरबीआई गवर्नर के बयान के अनुसार, रिज़र्व बैंक का प्रयास एक प्रभावी तरलता प्रबंधन ढांचा तैयार करना है जो अर्थव्यवस्था के अनुरूप हो और महामारी से उभरी हो और एक नवजात लेकिन मजबूत प्राप्ति हो।

आरबीआई का उदार रुख / मौद्रिक सहजता

वस्तुतः समायोजन शब्द का अर्थ है किसी की इच्छाओं या जरूरतों के लिए तैयार होना।

यह तब होता है जब एक केंद्रीय बैंक (आरबीआई) आर्थिक विकास धीमा होने पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समग्र मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने का प्रयास करता है। मुख्य उद्देश्य खर्च बढ़ाना है।

राष्ट्रीय आय और मुद्रा की मांग के अनुरूप मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि की अनुमति देने के लिए समायोजनात्मक मौद्रिक नीति लागू की जाती है। इसे "आसान मौद्रिक नीति" या लूज क्रेडिट के रूप में भी जाना जाता है।

जब अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है, तो केंद्रीय बैंक (RBI) अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए एक उदार मौद्रिक नीति लागू कर सकता है। यह ब्याज दरों में लगातार कमी करता है, जिससे उधार लेने में लागत सस्ती हो जाती है।

यह व्यवसायों के लिए उधार लेना आसान बनाता है, जो निवेश और संचालन के विस्तार को प्रोत्साहित करता है। मौद्रिक सहजता का तात्कालिक परिणाम आय तौर पर स्टॉक की कीमतों में वृद्धि है। मध्यम अवधि में, यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

3. फीचर फोन यूजर्स के लिए यूपीआई का विस्तार करेगा आरबीआई (Dec. 9, 2021)

मुख्य बातें:-

- फीचर फोन यूजर्स के लिए जल्द ही UPI सुविधा का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) छोटे मूल्य के भुगतान के लिए लेनदेन की मात्रा के मामले में देश में सबसे बड़ा खुदरा भुगतान प्रणाली - केवल स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध है।
- यह डिजिटल भुगतान को और सरल करने और उन्हें अधिक समावेशी बनाने, उपभोक्ताओं के लिए लेनदेन को आसान बनाने, वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा ग्राहकों की अधिक भागीदारी की सुविधा और सेवा प्रदाताओं की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।
- यह खुदरा भुगतान पर आरबीआई के नियामक सैंडबॉक्स से नवीन उत्पादों का लाभ उठाकर किया जाएगा।
- नियामक ने यूपीआई अनुप्रयोगों में 'ऑन डिवाइस' वॉलेट के माध्यम से छोटे मूल्य के लेनदेन के लिए प्रक्रिया प्रवाह को सरल बनाने का भी प्रस्ताव दिया है।
- आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड, कार्ड और वॉलेट यूपीआई और इसी तरह के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए ग्राहकों द्वारा किए गए विभिन्न शुल्कों पर एक चर्चा पत्र जारी करने का भी निर्णय लिया।
- आरबीआई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) का अनावरण करने की भी योजना बना रहा है, लेकिन भौतिक मुद्रा और नकली मुद्रा की समस्या के समाधान, साइबर सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी की चुनौतियों के बारे में चिंतित है।

हालांकि यूपीआई वर्चुअल भुगतान पते का उपयोग करते हुए एक 3 स्तरीय प्रमाणीकरण प्रणाली का उपयोग करता है, फिर भी साइबर सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी की चुनौती है।

आरबीआई नियामक सैंडबॉक्स:-

रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (आरएस) आमतौर पर नियंत्रित/परीक्षण नियामक वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं के लाइव परीक्षण को संदर्भित करता है जिसके लिए नियामक परीक्षण के सीमित के उद्देश्य के लिए कुछ नियामक छूट की अनुमति दे सकते हैं । आरएस नियामक, नवप्रवर्तनकर्ताओं, वित्तीय सेवा प्रदाताओं (प्रौद्योगिकी के संभावित नियोक्ता के रूप में) और ग्राहकों (अंतिम उपयोगकर्ताओं के रूप में) को नए वित्तीय नवाचारों के लाभों और जोखिमों पर साक्ष्य एकत्र करने के लिए फील्ड परीक्षण करने की अनुमति देता है, जबकि सावधानीपूर्वक निगरानी करनी हैं।

यह नियामक के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़ने और नवाचार-उत्तरदायी नियमों को विकसित करने के लिए एक संरचित अवसर प्रदान कर सकता है जो प्रासंगिक, कम लागत वाले वित्तीय उत्पादों के वितरण की सुविधा प्रदान करता है। आरएस एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो अधिक गतिशील, साक्ष्य-आधारित नियामक वातावरण को सक्षम बनाता है जो उभरती प्रौद्योगिकियों और विकसित करना हैं।

उद्देश्यों

- आरएस का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं में जिम्मेदार नवाचार , दक्षता को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है।
- आरएस, इसके मूल में, बाजार सहभागियों के लिए एक जीवंत वातावरण में ग्राहकों के साथ नए उत्पादों, सेवाओं या व्यापार मॉडल का परीक्षण करने के लिए एक औपचारिक नियामक कार्यक्रम है, जो कुछ सुरक्षा उपायों और निरीक्षण के अधीन है।
- आरएस के तहत शुरू की जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सेवा में नई या उभरती हुई तकनीक, या मौजूदा तकनीक का एक अभिनव तरीके से उपयोग में शामिल होना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए तथा उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना चाहिए।

ओन डिवाइस वॉलेट

ऑन डिवाइस वॉलेट या मोबाइल वॉलेट एक वर्चुअल वॉलेट है जो मोबाइल डिवाइस पर भुगतान कार्ड की जानकारी संग्रहीत करता है। ये उपयोगकर्ता के लिए इन-स्टोर भुगतान करने का एक सुविधाजनक तरीका है और मोबाइल वॉलेट सेवा प्रदाता के साथ सूचीबद्ध व्यापारियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे - ऐप्पल वॉलेट, सैमसंग पे

वर्तमान आरबीआई गवर्नर - शक्तिकांत दास

वर्तमान एनपीसीआई प्रमुख - दिलीप असबे

4. सिटी यूनियन बैंक ने भुगतान कीचेन "ऑन द गो" लॉन्च किया (Dec. 8, 2021)

- निजी क्षेत्र के ऋणदाता सिटी यूनियन बैंक (CUB), ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर शेषसाई के सहयोग से डेबिट कार्ड के लिए **'ऑन-द-गो' कॉन्टैक्टलेस वियरेबल कीचेन का अनावरण किया है।**
- बैंक के अनुसार, यह उपकरण ग्राहकों को बिना पिन डाले सभी RuPay सक्षम पॉइंट-ऑफ-सेल उपकरणों में 5,000 रुपये तक का तेजी से भुगतान करने में सक्षम बनाएगा।
- ₹5,000 से अधिक के भुगतान के लिए, ग्राहकों को टैप करना होगा और फिर पिन डालना होगा,
- खर्च की सीमा निर्धारित करने, नेट बैंकिंग के माध्यम से उपयोग करने और सिटी यूनियन बैंक(सीयूबी) के ऑल-इन-वन मोबाइल एप की सुविधाओं के साथ तेजी से चेक आउट और कतार में कम प्रतीक्षा करने पड़ेगा विशेष रूप से युवा पीढ़ी और छात्रों के बीच डिजिटल भुगतान के व्यवहार में वृद्धि होगी।

सिटी यूनियन बैंक का मुख्यालय: कुंभकोणम, तमिलनाडु

5. एशियाई विकास बैंक भारत को ऋण प्रदान करेगा (Dec. 8, 2021)

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक(एडीबी) ने भारत में परियोजनाओं के लिए ऋण के लिए दो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं

- **एडीबी** उत्तराखंड राज्य में देहरादून और नैनीताल शहरों में सुरक्षित और सस्ती पेयजल आपूर्ति और शहरो में समावेशी स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए **$125 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा।**
- यह **तमिलनाडु** राज्य में शहरी गरीबों के लिए समावेशी, लचीला और टिकाऊ आवास तक पहुंच प्रदान करने के लिए **$150 मिलियन का ऋण** भी प्रदान करेगा।

एशियाई विकास बैंक

1963 में एशिया और पूर्वी एशियाई देशों लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा आयोजित एशियाई आर्थिक सहयोग पर पहले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित होने के बाद 1966 में इसकी स्थापना की गई थी।

एडीबी की कल्पना 1960 के दशक की शुरुआत में एक वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी जो चरित्र में एशियाई होगा और दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देगा।

1966 में बैंक की स्थापना के समय मूल रूप से 31 सदस्य थे और अब इसके 68 सदस्य हैं - जिनमें से 49 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं।

भारत एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है

एडीबी का मुख्यालय:**मांडलुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस**

एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष: **जापान के मासत्सुगु असाकावा**

6. एमएसएमई क्षेत्र के विनिर्माण का योगदान (Dec. 7, 2021)

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नारायण राणे ने राज्यसभा को एक बयान में भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान के बारे में जानकारी दी।

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अखिल भारतीय विनिर्माण सकल मूल्य उत्पादन में एमएसएमई विनिर्माण की हिस्सेदारी क्रमशः 36.9% और 36.9% थी।

2019-20 और 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय निर्यात में निर्दिष्ट MSME संबंधित उत्पादों के निर्यात की हिस्सेदारी क्रमशः 49.8% और 49.4% थी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा

सूक्ष्म उद्यम: सूक्ष्म उद्यम एक ऐसा उद्यम है जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश ₹1 करोड़ से अधिक नहीं है और कारोबार ₹5 करोड़ से अधिक नहीं है

लघु उद्यम: लघु उद्यम एक ऐसा उद्यम है जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश ₹10 करोड़ से अधिक नहीं है और कारोबार ₹50 करोड़ से अधिक नहीं है

मध्यम उद्यम: मध्यम उद्यम एक ऐसा उद्यम है जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश ₹50 करोड़ से अधिक नहीं है और कारोबार ₹250 करोड़ से अधिक नहीं है

7. जुलाई-सितंबर 2021-22 (दूसरी तिमाही) में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.4% रही (Dec. 1, 2021)

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत है , ने 2021-22 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के संबंध में आर्थिक आंकड़े जारी किए हैं।

विशेषताएँ

- 2021-22 की दूसरी तिमाही में लगातार स्थिर मूल्यों (2011-12) पर सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) में **8.4 प्रतिशत की** वृद्धि हुई है।
- 2021-22 की दूसरी तिमाही में लगातार स्थिर मूल्यों (2011-12) पर सकल घरेलू उत्पाद 35.73 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 32.97 लाख करोड़ रुपये।
- 2020-21 की दूसरी तिमाही में मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित या ग्रॉस वैल्यू एडेड (जीवीए) 2021-22 में 32.89 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 30.32 लाख करोड़ रुपये रहा था, **इसे 8.5** प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है।
- पहली तिमाही (अप्रैल से जून) 2021 में जीडीपी विकास दर 20.1% थी।
- चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीने में विकास दर 13.7% रही।